International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार सृजन की भूमिका: इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन

Dr. Abhay Pathak
Professor (Department of Commerce), Swami Vivekanand Government Commerce College, Ratlam (MP)
Monica Bhawar
Research Scholar (Faculty of Commerce), Vikram University, Ujjain (MP)

संक्षेप

इंदौर जिले में सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म उद्यम सीमित संसाधनों के साथ संचालित होते हुए भी रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं और समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और अल्प शिक्षित व्यक्तियों, को आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। यह अध्ययन सूक्ष्म उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन के स्वरूप और गुणवत्ता का विश्लेषण करता है, जिसमें आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, और कौशल जैसे कारकों का प्रभाव शामिल है। शोध में यह पाया गया कि सूक्ष्म उद्यम न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में भी योगदान करते हैं। महिला उद्यमियों और श्रमिकों की भागीदारी ने सामाजिक संतुलन और समानता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही, युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिससे उनकी उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार हुआ। शोध ने यह भी उजागर किया कि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी नीतियों, वित्तीय सहायता, और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष निकला कि सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास को नई दिशा दी जा सकती है। यह अध्ययन सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता और उनकी चुनौतियों को समझने के लिए एक प्रभावी आधार प्रदान करता है

संकेत शब्द: सूक्ष्म उद्यम, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, सरकारी नीतियाँ।

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूक्ष्म व्यवसाय को रोजगार का प्रमुख स्रोत और आर्थिक विकास में बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है, इस क्षेत्र को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सूक्ष्म उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रोजगार, प्रतिस्पर्धा के मामले में जनता का समर्थन करते हैं और अक्सर नवाचार में भी परिणाम देते हैं। वे सूक्ष्म स्तर पर सुदृढ़ अर्थशास्त्र के भी अच्छे उदाहरण हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में, ये सूक्ष्म उद्यम अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये गरीब और अशिक्षित ग्रामीण एवं शहरी लोगों के लिए कमाई का एक स्रोत हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देकर और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने दायरे का विस्तार कर रहे हैं, घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं।

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि यह लगभग 30 मिलियन इकाइयों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दे रहा है, लगभग 70 मिलियन रोजगार पैदा कर रहा है, 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत योगदान दे रहा है और लगभग 40 प्रतिशत निर्यात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। यह क्षेत्र अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देश तेज और समावेशी विकास एजेंडे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा, यह एमएसएमई क्षेत्र ही है जो 2022 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को मौजूदा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्ष्य को साकार करने में मदद कर सकता है।

अतः बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए स्व–रोजगार सृजन ही संभव और उपयुक्त तरीका है। सूक्ष्म स्तरीय व्यवसाय के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन संभव हो सकेगा। ऐसा व्यवसाय रोजगार पैदा करता है यदि उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने और विकसित करने के लिए स्वस्थ वातावरण मिले। शहरी क्षेत्र की तुलना में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर के उद्यम स्थापित करने की इतनी क्षमता है क्योंकि इस क्षेत्र में मानव संसाधन, कच्ची सामग्री, मुख्य श्रम लागत सहित प्राकृतिक संसाधन हैं और उत्पादित वस्तुओं को बेचने और उसी बाजार से कच्ची सामग्री खरीदने के लिए आसानी से उपलब्ध स्थानीय बाजार है। इस दृष्टि से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नए व्यवसाय बनाने की इतनी ताकत है और एमएसएमई विकास से संबंधित सरकार की नई नीतियां, अधिनियम, कार्यक्रम और योजनाएं निश्चित रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में सूक्ष्म उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन की भूमिका का विश्लेषण इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में द्वितीयक आंकड़ों य के आधार पर किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसके अंतर्गत इंदौर जिले में कार्यरत सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जिला उद्योग केंद्र तथा आर्थिक

सर्वेक्षण जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टए सांख्यिकीय पत्रकए और अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

सूक्ष्म उद्यमों के विकास और उनके द्वारा सृजित रोजगार के प्रवृत्तिगत परिवर्तन यजतमदक ंदंसलेपेद्ध को समझा जा सके। आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशतए औसतए तथा वृद्धि दर यहतवूजी तंजमद्ध जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से किया गया है। इसके अतिरिक्तए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यच्डम्ळच्द्धए मुद्रा योजनाए और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रोजगार सृजन पर भी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य इंदौर जिले में सूक्ष्म उद्यमों की वास्तविक स्थितिए उनकी रोजगार सृजन क्षमताए और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में उनके योगदान का आकलन करना है। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग विश्वसनीयताए तुलनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु किया गया हैए जिससे परिणाम नीति निर्माण और स्थानीय आर्थिक नियोजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास का अध्ययन

पंचवर्षीय योजनावधि में उद्योगों का विकास :—

भारत में संचालित की जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य उद्योगों के विकास द्वारा संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। सिंतबर 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों के बीच औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्या तथा क्षेत्रीय असंतुलन के अध्ययन के लिए कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया गया था। योजनावधि के दौरान उद्योगों के विकास को तीन चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण ;1951.65द्ध जो कि औद्योगिक विकास को सृदृढ़ करने पर आधारित था। द्वितीय चरण ;1965.80द्ध में धीमी औद्योगिक प्रगति का समय रहा था। इस अवधि में सूखा, 1965, 1971 का युद्ध तथा 1973 में तेल संकट आदि के कारण घटती आर्थिक वृद्वि दर दर्ज की गई थी। तृतीय चरण ;1981.1991द्ध का समय औद्योगिक क्षेत्र में पुनरोंत्थान का रहा। 1991 की नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाने के साथ—साथ विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया।

पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक विकास के लिए परिव्यय की स्थिति

पंचवर्षीय योजना	योजनावधि	कुल परिव्यय	एस.एस.आई / एमएसएमई को	कुल परिव्यय में लघु उद्योग / एमएसएमई

			आवंटन	का प्रतिशत हिस्सा
प्रथम योजना	1951—1956	1,960	5.2	0.27
दूसरी योजना	1956—1961	4,672	56	1.2
तीसरी योजना	1961—1966	8,577	113.06	1.32
वार्षिक योजना	1966—1969	6,625	53.48	0.81
चौथी योजना	1969—1974	15,779	96.19	0.61
पाचवीं योजना	1974—1979	39,426	221.74	0.56
वार्षिक योजना	1979—1980	12,177	104.81	0.86
छठवीं योजना	1980—1985	1,09,292	616.1	0.56
सातवीं योजना	1985—1990	1,80,000	1120.51	0.62
आठवीं योजना	1992—1997	4,34,100	1629.55	0.66
नौवीं योजना	1997—2000	8,59,200	4303.85	0.5
दसवीं योजना	2002—2007	18,65,700	5534	0.3
ग्यारहवीं योजना	2007—2012	10,96,890	10168	0.93
बारहवीं योजना	2012—2017	16,33,111	14.455.00	0.87

पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक विकास के लिए परिव्यय की स्थिति

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

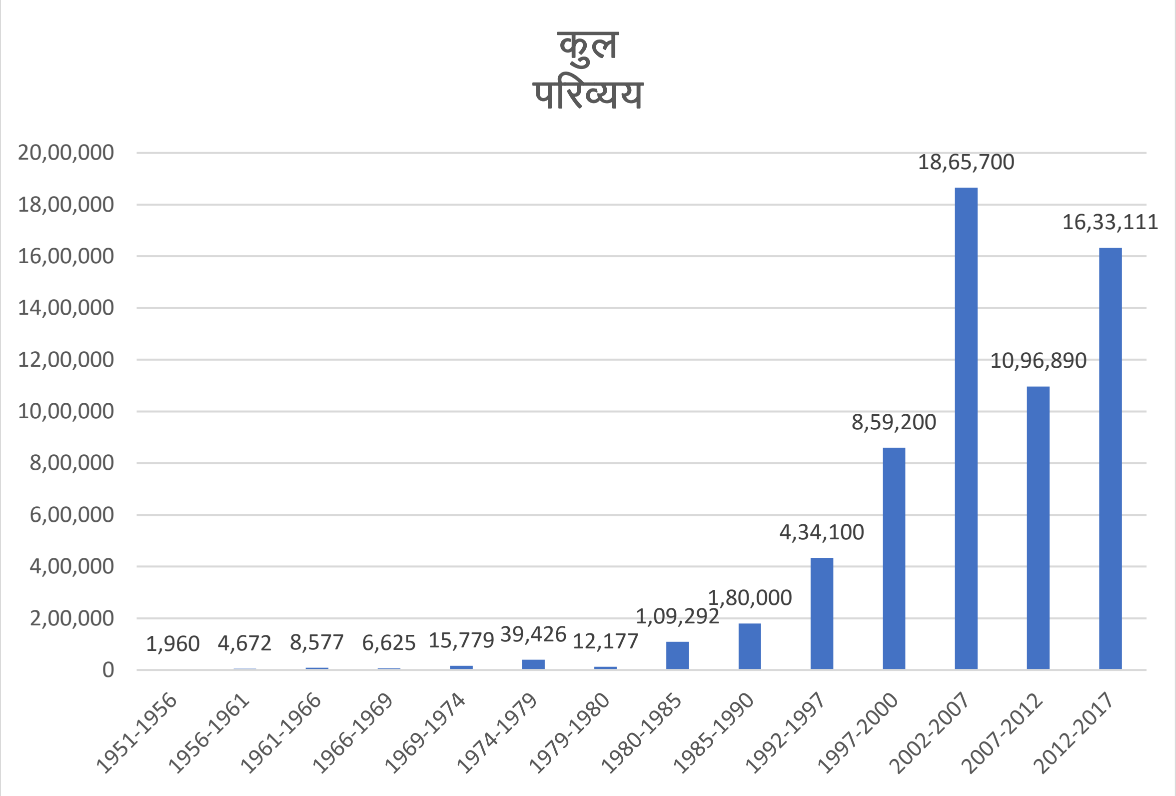

उपरोक्त तालिका संख्यके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है, कि देश में उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान दिया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु परिव्यय को रखा गया। इन योजनाओं में कुल परिव्यय सबसे अधिक दसवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया जबकि लघु स्तरीय उद्योगों एवं एमएसएमई क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक तीसरी पचवषीर्य योजना में प्रदर्शित हो रहा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी, परन्तु इस योजना में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता को अनुभव किया गया और औद्योगिक विकास की नींव रखी गई। इस योजना में रेशम उत्पादन और कयर सहित लघु उद्योगों के विकास में सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना की गयी। इसके साथ ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार पंजीकृत इकाईयों की स्थिति :–

निम्न तालिका संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वितरण पंजीकरण के आधार पर किया गया है। औद्योगिक इकाईयों के पंजीकरण का अध्ययन अक्टूबर 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2020 से जून 2020 के मध्य किया गया है :–

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार पंजीकृत इकाईयों का वितरण

उद्यम	वर्षवार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण						कुल
	2015—16	2016— 17	2017— 18	2018— 19	2019—20	2020—21	
सूक्ष्म उद्यम	420665	2138558	1342934	1867931	2248730	943605	8962423
लघु उद्यम	71151	217461	167231	242350	302299	219714	1220206
मध्यम उद्यम	2688	8779	6743	9463	11229	10937	49839
कुल	494504	2364798	1516908	2119744	2562258	1174256	10232468

स्त्रोत— **dcmsme.gov.in**

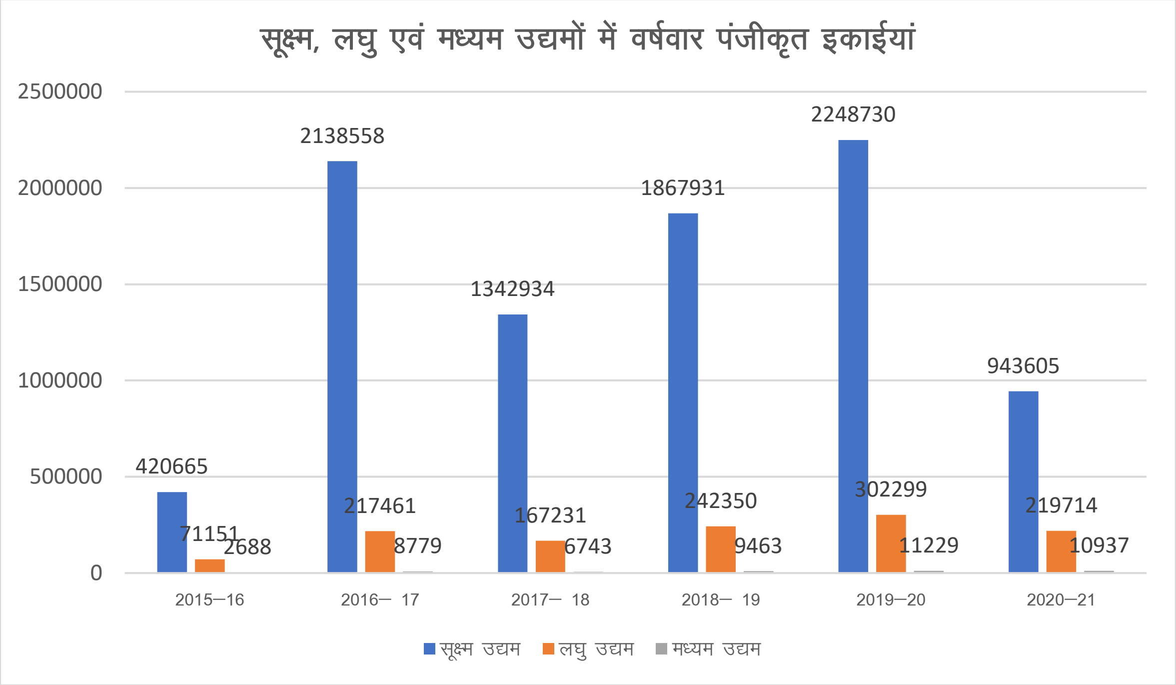

उपरोक्त तालिका संख्यके अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सबसे अधिक औद्योगिक इकाईयां वर्ष 2019—20 में पंजीकृत हुई है, जबकि सबसे कम वर्ष 2015—16 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण हुआ है। सूक्ष्म उद्योगों में सम्मिलित पंजीकृत इकाईयां सर्वाधिक प्रदर्शित होती है, तथा सबसे कम मध्यम उद्योगों की औद्योगिक इकाईयां हैं, जिनका पंजीकरण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की तुलना में काफी कम हुआ है।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार रोजगार का वितरण :—

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

निम्न तालिका संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वितरण रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। पंजीकरण औद्योगिक इकाईयों का अध्ययन अक्टूबर 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2020 से जून 2020 के मध्य किया गया है :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार रोजगार का वितरण

उद्यम	वर्षवार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में रोजगार						कुल
	2015– 16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	
सूक्ष्म उद्यम	1833804	7733309	5218236	7470203	8740985	4027290	35023827
लघु उद्यम	1282880	4295498	2837232	3670852	4007839	2730236	18824537
मध्यम उद्यम	224393	882358	592294	702002	790073	722980	3914100
कुल	3341077	12911165	8647762	11843057	13538897	7480506	57762464

स्त्रोत– **dcmsme.gov.in**

चित्र क्र 4.3

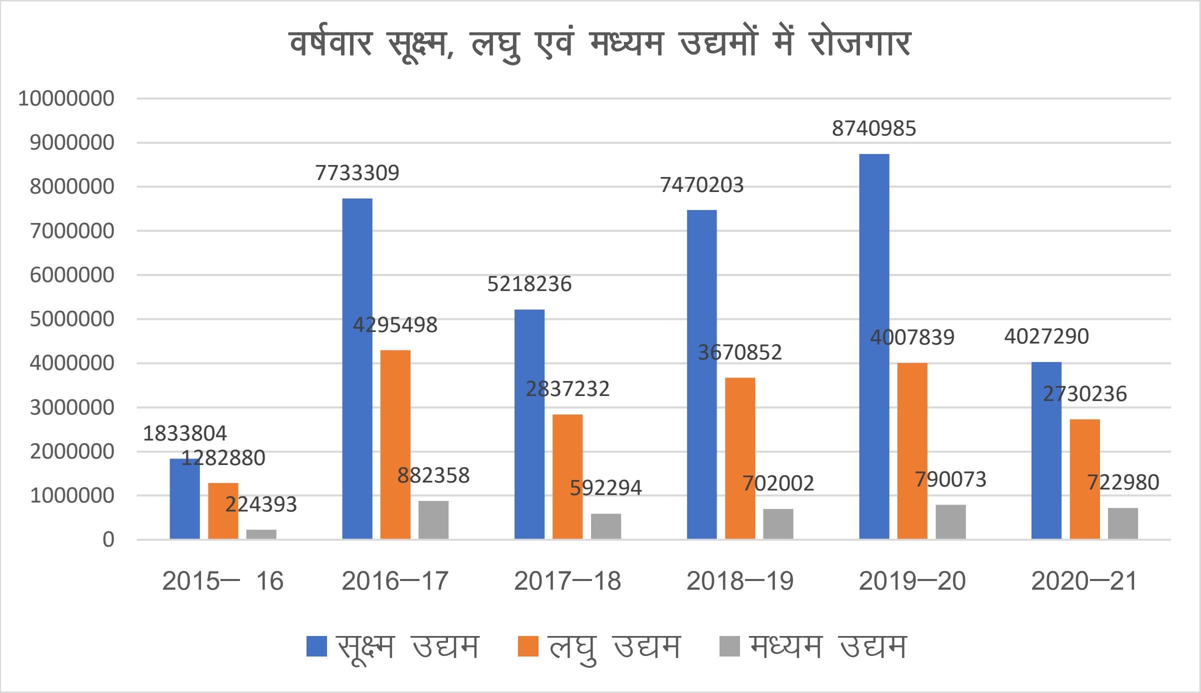

उपरोक्त तालिका संख्या 4.3 स्पष्ट करती है, कि सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार सृजन करने की क्षमता सबसे अधिक सूक्ष्म उद्योगों में प्रदर्शित होती है। सूक्ष्म उद्योगों में रोजगार में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक वर्ष 2019–20 में है, जबकि वर्ष 2015–16 में सूक्ष्म उद्योगों में सबसे कम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म उद्योगों के बाद रोजगार

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

उपलब्ध कराने में लघु उद्योगों की भूमिका प्रमुख है। लघु उद्योगों में वर्ष 2016—17 में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि वर्ष 2015—16 में रोजगार बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त था। अर्थात् सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षवार महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार निवेश की स्थिति :—

निम्न तालिका संख्या त्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वितरण निवेश के आधार पर किया गया है। औद्योगिक इकाईयों के निवेश का अध्ययन अक्टूबर 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2020 से जून 2020 के मध्य किया गया है :—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार निवेश का वितरण

उद्यम	वर्षवार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में निवेश का वितरण (लाख में)						कुल
	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	
सूक्ष्म उद्यम	2056066	8158889	6169589	8385448	9793744	4828964	39392700
लघु उद्यम	5422338	16372199	11424646	14721656	15942568	11035377	74918784
मध्यम उद्यम	1783351	5785309	4301675	5816000	6360207	5674291	29720833
कुल	9261755	30316397	21895910	28923104	32096519	21538632	144032317

स्त्रोत— **dcmsme.gov.in**

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

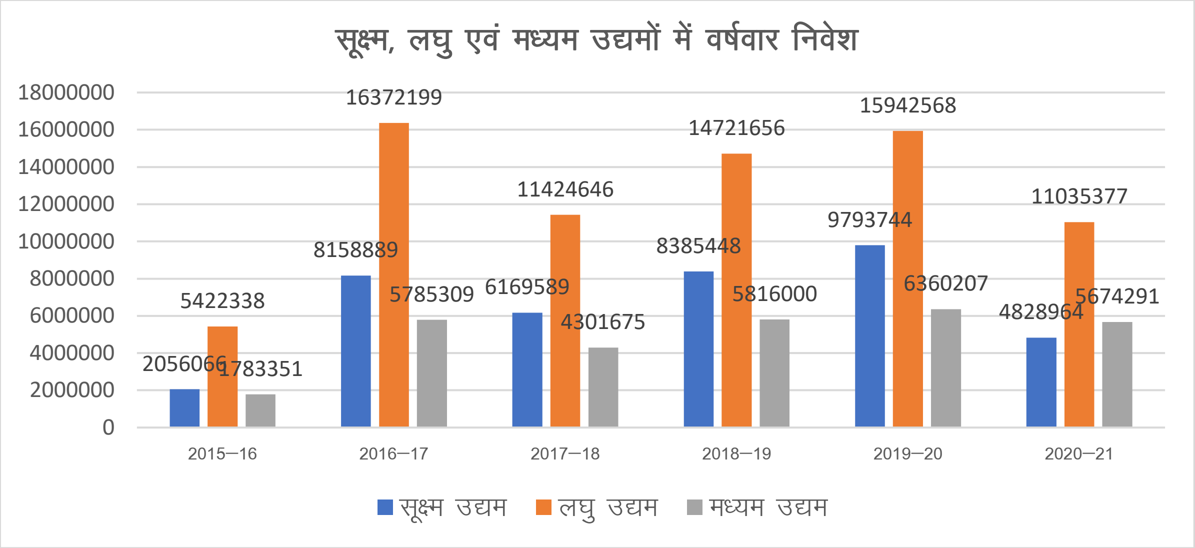

उपरोक्त तालिका संख्याएवं रेखाचित्र के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में निवेश सबसे अधिक लघु उद्योगों में किया गया है। लघु उद्यमों में सबसे अधिक निवेश वर्ष 2016–17 में किया गया है, जबकि वर्ष 2015–16 में निवेश राशि का स्तर सबसे कम प्रदर्शित होता है। वर्ष वार सर्वाधिक निवेश 2019–20 में किया गया है, जबकि सबसे कम निवेश वर्ष 2015–16 में किया गया।

आर्थिक समीक्षा की रिपार्ट (2020–21) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 6 करोड़ से भी अधिक है। इस क्षेत्र में जी.डी.पी. का लगभग 30 प्रतिशत का योगदान है, तथा सुदृढ़ व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में देश के आयात का आधे हिस्से में इस क्षेत्र का योगदान है।

वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड–19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट की सहायता प्रदान करायी गयी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का 3 लाख करोड़ का बिना किसी जमानत के आटोमैटिक ऋण दिया गया। तथा दबाव ग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 20,000 करोड़ रूपयों का गौण–ऋण उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई फंड आफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इनफ्यूजन किया गया। एमएसएमई के लिए ई–मार्केट लिंकेज, व्यापार, मेलों और प्रदर्शनियों का भी प्रावधान किया गया।

एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना–2006–07 की रिपोर्ट (2011) के अनुसार एमएसएमई की पहली गणना वर्ष 1973–74 में की गयी, जिसमें 2.58 लाख लघु स्तरीय

उद्योग पंजीकृत थे। किन्तु 1.4 लाख इकाईयां ही कार्यरत पायी गयी। दूसरी गणना वर्ष 1990—92 में संपन्न की गयी। जिसमें 9.87 लाख लघु उद्योग पंजीकृत थे। 5.82 लाख इकाईयां ही कार्यरत पायी गयी। तीसरी गणना में 22.62 लाख इकाईयों का सर्वेक्षण 31 मार्च 2001 तक किया गया, जिसमें 13.75 लाख इकाईयां कार्यशील पायी गयी। चतुर्थ गणना वर्ष 2006—07 के अनुसार 198.74 लाख इकाईयां पंजीकृत थी, जिसमें 119.68 ग्रामीण एवं 79.05 लाख शहरी क्षेत्र में पंजीकृत थी।

मध्यप्रदेश राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थिति :—

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगीकरण का विकास राज्य की स्थापना के बाद से माना जाता है। मध्यप्रदेश राज्य में पारंपरिक उद्योगों का इतिहास रहा है। पारंपरिक उद्योगों में हथकरघा, हस्तकला उद्योग और खादी व ग्रामोद्योग आधारित उद्योग सम्मिलित हैं। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। वर्ष 2000 तक मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक दृष्टि से अविकसित था। राज्य में उद्योगों का विकास राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के बाद से शुरू हुआ। मध्यप्रदेश राज्य में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अतः सूक्ष्म उद्योगों का अधिकतर विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है।

मध्यप्रदेश राज्य में वनाधारित व कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएँ अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक है। मध्यप्रदेश में वन, जल, खनिज इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राज्य की अर्थव्यवस्था में वन, कृषि, पर्यटन, जल, खनिज क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण निभाते हैं, जिस कारण यह सभी प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं।

मध्यप्रदेश राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार पंजीकृत इकाईयों की स्थिति

क्र.	वर्ष	पंजीकृत इकाईयों की स्थिति
1.	2015—16	48179
2.	2016—17	87071
3.	2017—18	206142
4.	2018—19	297595
5.	2019—20	288479
6.	2020—21	187000

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

7.	2021–22	246000
8.	2022–23	354000

स्त्रोत– https://www.mpmsme.gov.in/

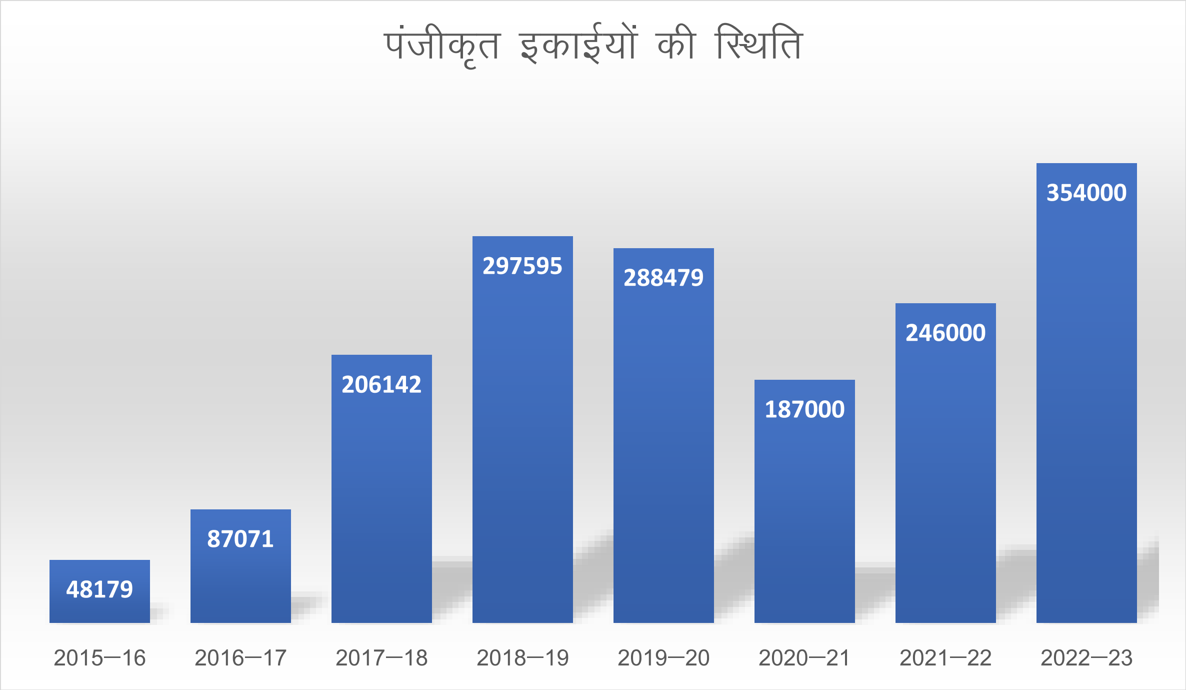

तालिका क्र. में 2015–16 से 2022–23 तक 8 वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दर्शाता है।

वर्ष 2015–16 में कुल 48,179 एमएसएमई पंजीकृत हुए, 2016–17 में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 87,071 हो गई। अगले वर्ष, 2017–18 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में पर्याप्त उछाल आया और यह 206,142 तक पहुंच गई।

समंक के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018–19 में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में वृद्धि जारी रही। वर्ष 2019–20 में, 288,479 पंजीकृत इकाइयों के साथ पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। कोविड महामारी के दौरान 2020–2021 में पंजीकृत एमएसएमई में काफी कमी देखी गई, केवल 1.87 लाख उद्यम पंजीकृत हुए। हालाँकि, अगले वर्ष, 2021–2022 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में मामूली वृद्धि हुई और यह 2.46 लाख हो गई। अंततः, वर्ष 2022–2023 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 3.54 लाख तक पहुंच गई। प्रदान किया गया समंक, दी गई अवधि में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या के आंकड़ों में उतार–चढ़ाव दर्शाता है। 2015–16 से 2022–23

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

तक 8 वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मामले में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया

मध्यप्रदेश राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार रोजगार का वितरण

क्र.	वर्ष	रोजगार का वितरण	प्रतिशत वृद्धि /कमी
1.	2015–16	194761	–
2.	2016–17	363812	86.80 प्रतिशत वृद्धि
3.	2017–18	596990	64.09 प्रतिशत वृद्धि
4.	2018–19	1030084	72.55 प्रतिशत वृद्धि
5.	2019–20	993876	–3.52 प्रतिशत कमी
6.	2020–21	1499000	50.80 प्रतिशत वृद्धि
7.	2021–22	1408000	–6.07 प्रतिशत कमी
8.	2022–23	1833000	30.18 प्रतिशत वृद्धि

स्त्रोत– https://www.mpmsme.gov.in/

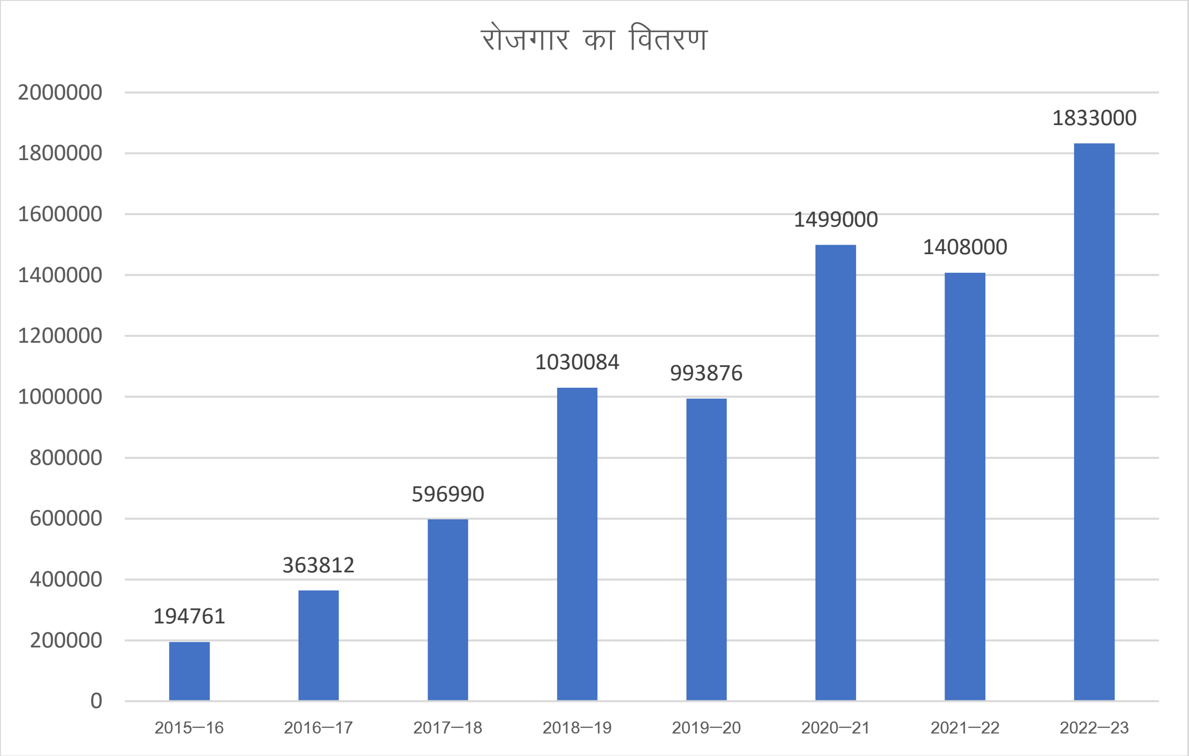

तलिका क्र. 4.6 में 2015–16 से 2022–23 तक 8 वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में उत्पन्न रोजगार के बारे में सटीक आंकड़े प्रदान

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

किए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन को भी रेखांकित किया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल 48,179 एमएसएमई पंजीकृत हुए, जिसमें 194,761 रोजगार के अवसर पैदा हुए।

2016–17 से आगे बढ़ते हुए, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। पंजीकृत एमएसएमई की संख्या बढ़कर 87,071 हो गई। परिणामस्वरूप, एमएसएमई क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार बढ़कर 363,812 हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 86.80 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।

अगले वर्ष, 2017–18 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में पर्याप्त उछाल आया और यह 206,142 तक पहुंच गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में रोजगार बढ़कर 596,990 हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 64.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

समंक के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018–19 में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में वृद्धि जारी रही। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान उत्पन्न रोजगार एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया, कुल 1,030,084 नौकरियां पैदा हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष, 2019–20 में, 288,479 पंजीकृत इकाइयों के साथ पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। इस अवधि के दौरान रोजगार सृजन में 3.52 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे कुल 993,876 रोजगार के अवसर पैदा हुए।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में, 2.97 लाख पंजीकृत एमएसएमई थे, जिनमें लगभग 10.30 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था। अगले वर्ष, 2019–2020 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या घटकर 2.88 लाख हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 9.94 लाख व्यक्तियों को रोजगार में कमी आई। यह पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 3.50 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगले वर्ष, 2020–2021 में पंजीकृत एमएसएमई में काफी कमी देखी गई, केवल 1.87 लाख उद्यम पंजीकृत हुए। इस गिरावट के बावजूद, इस क्षेत्र में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 14.99 लाख व्यक्तियों तक पहुंच गया, जो रोजगार में 50.80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है।

हालाँकि, अगले वर्ष, 2021–2022 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में मामूली वृद्धि हुई और यह 2.46 लाख हो गई, लेकिन रोजगार के आंकड़ों में नकारात्मक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा, जो घटकर 14.08 लाख रह गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 6.07 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। अंततः, वर्ष 2022–2023 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 3.54 लाख तक पहुंच गई, और रोजगार के आंकड़ों में 18.33 लाख व्यक्तियों की वृद्धि देखी गई। यह रोजगार में 30.18 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है।

कुल मिलाकर, प्रदान किया गया समंक दी गई अवधि में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या और रोजगार के आंकड़ों में उतार–चढ़ाव दर्शाता है। जबकि रोजगार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलावों के उदाहरण थे, यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र ने 2020–2021 से 2022–2023 तक रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया।

मध्यप्रदेश राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्षवार निवेश (करोड़ों में) की स्थिति

क्र.	वर्ष	निवेश की स्थिति (करोड़ों में)	
1.	2015–16	5171.75	
2.	2016–17	9547.32	
3.	2017–18	14401.67	
4.	2018–19	19284.97	
5.	2019–20	19242.09	
विवरण	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**
दावों की संख्या	1189	1780	2551
सहायता दी गई	107.74	392.45	697.43

स्त्रोत– https://www.mpmsme.gov.in/

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

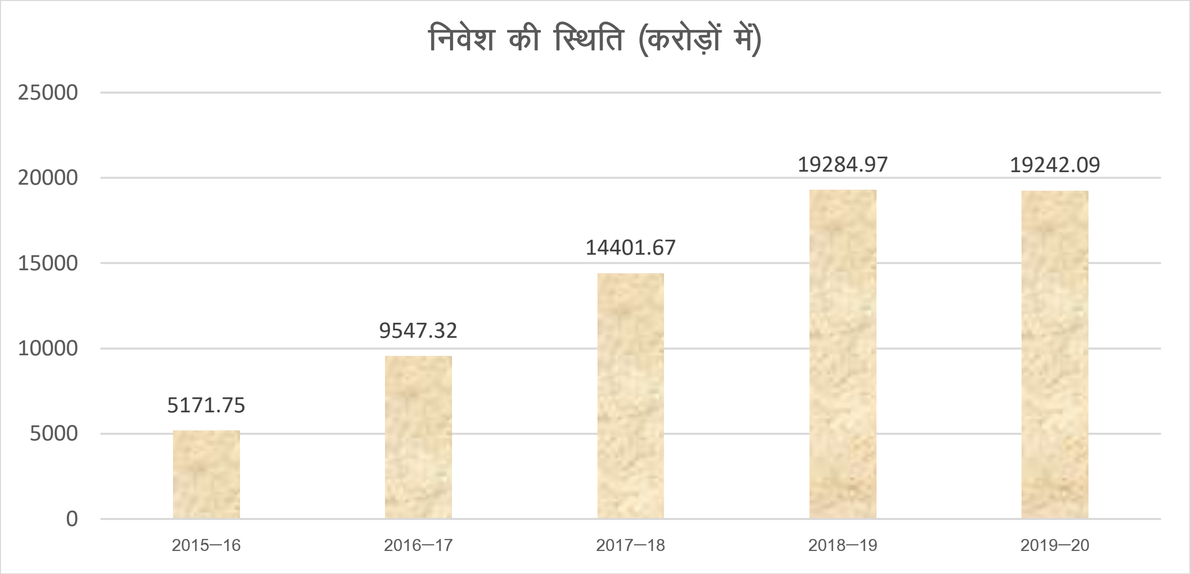

तलिका क्र. 4.7 में 2015–16 से 2019–20 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में किए गए निवेश (करोड़ों में) के बारे में सटीक आंकड़े प्रदान किए हैं। वर्ष 2015–16 में कुल 48,179 एमएसएमई पंजीकृत हुए, जिसमें 5,171.75 करोड़ का निवेश हुआ। 2016–17 से आगे बढ़ते हुए, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या और निवेश दोनों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। पंजीकृत एमएसएमई की संख्या बढ़कर 87,071 हो गई। इसके अनुरूप सेक्टर में निवेश बढ़कर 9,547.32 करोड़ हो गया। अगले वर्ष, 2017–18 में, पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में पर्याप्त उछाल आया और यह 206,142 तक पहुंच गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में निवेश बढ़कर 14,401.67 करोड़ हो गया।

समंक के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018–19 में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में वृद्धि जारी रही। इस क्षेत्र में किए गए निवेश में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो कि 19,284.97 करोड़ रुपये रही। अंत में, वर्ष, 2019–20 में, 288,479 पंजीकृत इकाइयों के साथ पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। इसीलिए निवेश थोड़ा कम होकर 19,242.09 करोड़ रह गया।

दिया गया समंक 2020–21 से 2022–23 वर्षों के लिए दावों की संख्या और दी गई सहायता की राशि को दर्शाता है। वर्ष 2020–21 में 1189 दावे एवं सहायता राशि 107.74 करोड़ प्राप्त हुई। वर्ष 2021–22 में 1780 दावे एवं सहायता राशि 392.45 करोड़ प्राप्त हुई वर्ष 2022–23 में 2551 दावे एवं सहायता राशि 697.43 करोड़ प्राप्त हुई। इस समंक से, हम देख सकते हैं कि दावों की संख्या साल–दर–साल बढ़ती रही है। 2021–22 और 2022–23 में दावों की संख्या में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी तरह, दी जाने वाली सहायता राशि भी साल–दर–साल बढ़ती रही है। 2021–22 और 2022–23 में दी गई सहायता की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, यह समंक बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में दावों की संख्या और दी जाने वाली सहायता राशि दोनों में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष में, प्रस्तुत आंकड़ों के कालानुक्रमिक विश्लेषण से पंजीकृत एमएसएमई की संख्या, क्षेत्र में किए गए निवेश और 8 वर्षों में उत्पन्न रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि का पता चलता है। हालाँकि, हाल के वर्ष में इन मापदंडों में मामूली गिरावट देखी गई है, जो आगे की शोध और विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा।

निष्कर्ष

इंदौर जिले (मध्यप्रदेश) में सूक्ष्म उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन की भूमिका पर किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सूक्ष्म उद्यम क्षेत्रीय और सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये उद्यम रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों, जैसे महिलाएं, युवा, और अल्प शिक्षित व्यक्तियों, को आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि सूक्ष्म उद्यमों के कारण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय स्तर पर गरीबी में कमी और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है। शोध में यह भी पाया गया कि रोजगार का स्वरूप और गुणवत्ता शैक्षणिक योग्यता, कौशल, और लिंग जैसे कारकों से प्रभावित होती है। महिला उद्यमियों और श्रमिकों की भागीदारी सूक्ष्म उद्यमों में अपेक्षाकृत अधिक देखी गई, जिससे सामाजिक संतुलन में सुधार होता है। इसके अलावा, सूक्ष्म उद्यमों ने युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार हुआ। यह निष्कर्ष निकला कि सूक्ष्म उद्यमों को और अधिक प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन्हें प्रोत्साहन के लिए सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह अध्ययन रोजगार सृजन की प्रक्रिया और सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका को बेहतर समझने में सहायक है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1. भानु शाली एस. जी. (1987)। उद्यमिता विकास, प्रथम संस्करण, हिमालय पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. देसाई वसंत (2008)। लघु उद्योगों का प्रबंधन, नई दिल्ली, भारत: हिमालय पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ISBN: 978-81-8488-080-9, पृष्ठ 1-675।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

3. डॉ. अरुण कुमार बी. (2020)। भारत में ग्रामीण विपणन, पब्लिश वर्ल्ड पब्लिकेशन, गुजरात।
4. रिचर्ड पी. ग्रीन, जेरोम काट्ज (2017)। उद्यमशील लघु व्यवसाय, मैकग्रा-हिल एजुकेशन, न्यूयॉर्क।
5. अनिल कुमार ठाकुर, प्रवीण शर्मा (संपादक) (2009)। सूक्ष्म ऋण और ग्रामीण विकास, डीप एंड डीप पब्लिकेशन, केरल।
6. अशोक झुनझुनवाला (2011)। आईसीटी पहलों के साथ ग्रामीण भारत को सक्षम करना, विशेष अंक, आईआईटीएम, चेन्नई।
7. ग्रिमशोल्म और पब्लेटे (2010)। सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (SME) की वृद्धि में बाधा डालने वाले आंतरिक और बाहरी कारक। 8 जून 2013 को एक्सेस किया गया। http://uu.divportal.org.pdf।
8. मायर्स, फ्रेडरिक एलन (1981)। विवाहित महिलाओं के रोजगार पर आर्थिक दबाव, पीएच.डी. शोध प्रबंध, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, अमेरिका।
9. शर्मा, बी.एल. और शर्मा, आर.सी. (2004)। "राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्था में डेयरी और फसल उद्यमों का योगदान", इंडियन जे. एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 59(3): पृष्ठ 608-609।
10. भवे, एस. सी. (1976)। पुणे क्षेत्र की लघु इकाइयों के विशेष संदर्भ में विपणन संगठन, नीति और प्रक्रियाएं, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे। कॉल नंबर: X:5/भवे 5।
11. पांडे, सुधीर (2012)। प्रबंधन कार्यों का उद्यमशीलता विकास पर प्रभाव - पुणे और उसके आसपास के छोटे और सूक्ष्म उद्यमों का अध्ययन, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, पृष्ठ 1-286।